units in West Bengal is steadily improving. Improvements have been effected in management and operations have been streamlined after take-over by Govt. With decentralisation and delegation of powers, there has been improvement in the speed of decision-making. Internal Audit and Vigilance Sections have been organised to effect economies and avoid waste.

देश में बिजली की सप्लाई में अवरोध

*655. **श्रीमती चन्द्रावती :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की सप्लाई में अवरोध का कारण खराब तारों का होना अथवा प्रशासन की अकुशलता है; और

(ख) सरकार इसकी सप्लाई में ऐसा अवरोध दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख). देश में बिजली की कमी का मुख्य कारण रहा है ; पहले से पर्याप्त आयोजन न किये जाने के परिणामस्वरूप विद्युत् उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होना और विगत काल में धन व संगठन की कमी तथा अन्य बातों के परिणामस्वरूप लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता।

2. इसके अलावा, जब भी बिजली की जबरन बन्दी होती है तब उस कमी को पूरा करने के लिए प्रणाली में स्पिनिंग रिजर्व न होने के कारण भी बिजली की सप्लाई में अवरोध आ जाते हैं।

3. बिजली की गड़बड़ी के अन्य कारणों में ये भी शामिल हैं :—बिजली की जबरन बन्दी, पारेषण और वितरण तारजालों में गतिरोध, और श्रम समस्याओं के कारण बिजली का उत्पादन धीमी गति से होना।

4. छठी योजना के अन्त तक बिजली की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने के लिए योजना बना रही है। बिजली की जबरन बन्दी की अवधि तथा इसकी घटनाओं की संख्या में कमी करने और विद्युत् उत्पादन अधिकतम करने के लिए पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त करने तथा वर्तमान यूनिटों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। बेहतर प्रचालन संबंधी कुशलता के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और वास्तविक प्रचालन में प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखकर उपस्करों के निर्माण में सुधार के लिए लगातार सुझाव दिये जा रहे हैं ताकि प्रचालन और उत्पादन इष्टतम हो।

5. नयी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए धन में वृद्धि की जा रही है। प्रणालियों में सुधार लाने के लिए भी स्कीमें शुरू की जा रही हैं।

"Warranty" Charges by Private Sector Television Set Manufacturers

*656. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:
SHRI ANANT DAVE:

Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether Government have seen a Press report appearing in the *Economic Times*, dated the 29th June, 1977 (New Delhi Edition) to the effect that the private sector television set manufacturers have decided to charge Rs. 300/- for "warranty";

(b) whether so far they were not charging anything for "warranty"; and